

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1559
जिसका उत्तर बुधवार, 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

खुदरा मुद्रास्फीति

1559. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर माह के 5.59% से बढ़कर अक्तूबर माह में 6.2% हो गई है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ने आम लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) : जी, हाँ।

(ख): अक्तूबर 2024 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य में वृद्धि का कारण यह रहा कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में लंबे समय तक मानसून की बारिश के परिणामस्वरूप खड़ी फसलों को नुकसान होने की वजह से सब्जियों की कीमत में वृद्धि हुई और यह भी कि कटी हुई फसल शीघ्र खराब हो जाती है। कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वे उत्पादन में मौसमी परिवर्तन, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीतिगत साधनों में परिवर्तन पर उचित निर्णय लिए जा सकें।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए संतुलित और लक्षित रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में, बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को भारत दाल ब्रांड के तहत किफायती कीमतों पर उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है। बफर स्टॉक से प्याज को थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से उच्च मूल्य उपभोक्ता केंद्रों में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केंद्रों पर स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। इन उपायों से दालें, चावल, आटा और प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है।

गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात् प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
